(i) to finalise a list of critical indicators of child survival and development which could be implemented in a phased manner; and

(ii) to prepare a work plan specifying tbe scope and details of the activities in different stages with targeted outputs, participating agents (institutions and persons responsible), time frame for implementation, mid-course review and conclusion of each state and budget requirements.

The Government has accepted the recommendation .

लोहे के स्लीपरों की ढुलाई के लिये टिस्को द्वारा उपयोग किये गये वैगन

263. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :**
डा० (श्रीमती) सरोजनी महिषी :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1977 से 1980 के बीच टिस्को जमशेदपुर ने रेल के वैगनों में लोहे के स्लीपरों को लाद कर भेजा था और उन्हें खाली दिखाकर काला बाजारी से करोड़ों रुपया कमाया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में रेलवे के अधिकारियों और मैसर्स टिस्को के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे वैगनों की संख्या कितनी है और इन वैगनों में अनुमानतः लोहे के कितने स्लीपरों का लदान किया गया और उसकी कीमत क्या थी ; और

(घ) क्या सरकार यह पता लगाने के लिये कि क्या यह काम अभी भी जारी है, कोई जांच करने का विचार रखती है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) 1977 से 1980 तक टिस्को द्वारा लोहे के स्लीपरों की जाली बुकिंग और रेलवे और टिस्को के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज किये गये किसी मामले की सूचना नहीं है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

264. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्रीमती कनक मुखर्जी :
श्री चिमनभाई मेहता :
श्री रामसिंहभाई पातलीया-भाई राठवा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा के मुख्य-मुख्य मुद्दे क्या थे ;

(ख) प्राथमिक, माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या शिक्षा नीति तैयार करने के बारे में कोई विचार-विमर्श हुआ था ; और

(घ) क्या सम्मेलन में हुई चर्चा का आधार देश की भावनात्मक एकता और अखण्डता था ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) राज्यों में संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, जो 23–24 जनवरी, 1986 को हुआ था, ने नई शिक्षा नीति से संबंधित प्राथमिकताओं पर चर्चा की और निम्नलिखित विषयों पर बल दिया :

(1) शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति का सृजन करना ।

(2) गैर-औपचारिक शिक्षा सहित प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना ।

(3) माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायीकरण ।